रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD NO D L -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 147] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 28, 2002/चैत्र 7, 1924

No. 147] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 28, 2002/CHAITRA 7, 1924

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2002

सा. का. नि. 237(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"सं. आ. 187

संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 2002

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 2002 है।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल, 2001 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, भारत की संचित निधि पर, निम्नलिखित राशियां भारित होंगी, जो नीचे विनिर्दिष्ट राज्यों में से प्रत्येक को राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में, प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट हैं।

	राज्य	रु. करोड़ में
	(1)	(2)
1.	अरुणाचल प्रदेश	209 73
2.	हिमाचल प्रदेश	851.85
3.	जम्मू-कश्मीर	1904.74
4.	मणिपुर	301.77
5.	मेघालय	280.86
6.	मिजोरम	280.14
7.	नागालैंड	572.87
8.	उड़ीसा	30.97
9.	राजस्थान	246.01
10.	सिक्किम	145.12
11.	त्रिपुरा	419.07
12.	पश्चिमी बंगाल	879.33

(2) उपपैरा (1) के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट राशियां, ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2001-02 के लिए सिफारिश की गई रकमों का 85 प्रतिशत है। ग्यारहवें वित्त आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में उपर्युक्त राज्यों के लिए सिफारिश किए गए अनुदानों के 15 प्रतिशत को रोक कर और उतना ही अंशदान केन्द्रीय सरकार से लेकर एक प्रोत्साहन निधि में जमा करने की सिफारिश की थी, जिसमें से सभी राज्यों को राजवित्तीय कार्यपालन के आधार पर अनुदान जारी किए जाएंगे।

(3) प्रत्येक राज्य के सामने यथा विनिर्दिष्ट निम्नलिखित अनुदानों की निकासी चालू वर्ष के दौरान राज्यों के राज्य वित्तीय निष्पादन के आधार पर प्रोत्साहन निधि से वर्ष 2000-01 दौरान की गई थी :—

	राज्य	रु. करोड़ में
	(1)	(2)
1.	आन्ध्र प्रदेश	47.94
2.	अरुणाचल प्रदेश	36.69
3.	हिमाचल प्रदेश	161.23
4.	जम्मू-कश्मीर	321.84
5.	कर्नाटक	32.29
6.	केरल	23.52
7.	महाराष्ट्र	55.55
8.	मणिपुर	54.38
9.	नागालैंड	97.22
10.	उड़ीसा	77.95
11.	राजस्थान	171.68
12.	त्रिपुरा	73.99
13.	पश्चिमी बंगाल	302.29

(4) उपपैरा (1) और (3) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, राज्यों को अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परन्तुकों में से प्रत्येक के अधीन संदेय किसी राशि या किन्हीं राशियों के अतिरिक्त होंगी।

के. आर. नारायणन,

राष्ट्रपति।''

[फा. सं. 19(1)/2002-विधायी-1]

के. एन. चतुर्वेदी, अपर सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2002

G.S.R. 237(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

"C.O. 187

The Constitution (Distribution of Revenues) Order, 2002

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 2002

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2001, as grants-in-aid of the revenues to each of the States specified below, the sums specified against it:—

	State	Rupees in crores
	(1)	(2)
1.	Arunachal Pradesh	209.73
2.	Himachal Pradesh	851.85
3.	Jammu and Kashmir	1904.74
4.	Manipur	301.77
5.	Meghalaya	280.86
6.	Mizoram	280.14
7	Nagaland	572.87
8.	Orissa	30.97
9.	Rajasthan	246.01
10.	Sikkim	145.12
11.	Tripura	419.07
12.	West Bengal	879.33

(2) The sums specified in column (2) of sub-paragraph (1) represent 85 per cent, of the amount recommended by the Eleventh Finance Commission for the year 2001-02. The Eleventh Finance Commission in its last report had recommended withholding of 15 per cent, of the grant recommended to the above States with matching contribution by the Central Government for crediting into an Incentive Fund from which fiscal performance based grants will be released to all the States.

(3) The following grants-in-aid as specified against each State were released during current year from Incentive Fund based on the fiscal performance of States during 2000-01.

	State	Rupees in crores
	(1)	(2)
1.	Andhra Pradesh	47.94
2.	Arunachal Pradesh	36.69
3.	Himachal Pradesh	161.23
4.	Jammu and Kashmir	321.84
5.	Karnataka	32.29
6.	Kerala	23.52
7.	Maharashtra	55.55
8.	Manipur	54.38
9.	Nagaland	97.22
10.	Orissa	77.95
11.	Rajasthan	171.68
12.	Tripura	73.99
13.	West Bengal	302.29

(4) Any sum or sums payable under sub-paragraphs (1) and (3) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

K. R. NARAYANAN,

PRESIDENT."

[F. No. 19(1)/2002-L.I.]

K. N. CHATURVEDI, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.